द बॉम्बे यूनीयन ऑफ जनरलिस्ट व अन्य

बनाम

द हिन्दू, बॉम्बे व अन्य

27 सितम्बर, 1961

(के. एन. वान्चू एवं जे.सी. शाह जे.जे.)

औद्योगिक विवाद-व्यक्तिगत विवाद-यदि और कब हो सकता है

औद्योगिक विवाद-औद्योगिक विवाद अधिनियम में सम्मिलित किया जाए, 1947 (1947 का 14),12 (6).

पहला प्रतिवादी, 'हिन्दू', बंबई, जो था, समाचार पत्र प्रतिष्ठान ने तीसरे की सेवाएँ समाप्त कर दीं, अपीलकर्ता ने इसके संवाददाता के रूप में और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, उसकी पुनः बहाली के लिए उत्तरार्द्ध का अनुरोध। उनका मामला था, बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स द्वारा उठाया और समर्थित, ए ट्रेड यूनियन, जिसकी सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी, अपनी आजीविका के लिए पत्रकारिता पर निर्भर हैं। वह नहीं था 'हिन्दू' के कर्मचारियों के किसी भी संघ द्वारा समर्थित, बम्बई, या इसके कई कामगार। सरकार ने हवाला दिया के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 12(5) के तहत न्यायनिर्णयन के लिए विवाद

का औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए संदर्भ को खारिज कर दिया कि विवाद केवल एक व्यक्तिगत विवाद था, 'हिंदू', बॉम्बे और तीसरे अपीलकर्ता के बीच के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या द्वारा समर्थित नहीं किया गया ।

'हिन्दू', बम्बई. अपील पर, माना गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रयोज्यता किसी व्यक्तिगत विवाद को किसी विवाद से अलग करना, काम करने वालों के एक समूह को शामिल करने को बाहर रखा गया है, जब तक कि काम करने वाले एक निकाय न हों या उनके एक बड़े वर्ग के रूप में व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं के साथ कारण सामान्य हैं

सेंट्रल प्रोविंस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बनाम रघुनाथ गोपाल.पटवर्धन (1956) एससीआर 956 और द न्यूजपेपर्स लिमिटेड। राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उ.प्र.(1957) एससीआर 754, का पालन किया।

संघ के सदस्य जो नियोक्ता के कर्मचारी नहीं थे जिनके विरुद्ध विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई थी, वे नहीं कर सके, उनके समर्थन से एक व्यक्तिगत विवाद को एक औद्योगिक विवाद में बदल दिया जाता है। वे व्यक्ति जिन्होंने इस उद्देश्य का समर्थन करना चाहा जिनको कार्यकर्ता के रुप में प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से होना चाहिए, विवाद में रुचि रखने वाले और ऐसे व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं थे एक ही नियोक्ता को इतना इच्छुक नहीं माना जा सकता।

इस संदर्भ में दिमाकुची चाय बागान के श्रमिक बनाम दिमाकुची का प्रबंधन टी एस्टेट (1958) एससीआर 1156, का अनुसरण किया गया।

प्रत्येक मामले में यह पता लगाने में कि क्या कोई व्यक्तिगत विवाद है, परीक्षण ने एक औद्योगिक विवाद का स्वरूप प्राप्त कर लिया था, क्या संदर्भ की तिथि पर विवाद था जिसको कामगारों के संघ द्वारा उठाया और समर्थित किया गया, नियोक्ता जिसके विरुद्ध विवाद उठाया गया था व्यक्तिगत कमर्चारी या ऐसे ही एक प्रशंसनीय संख्या द्वारा कामगार श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं था, के द्वारा बाद में समर्थन वापसी से प्रभावित न ही कर सका। वे कार्यकर्ता जिन्होंने मूल रूप से इस मुद्दे को प्रायोजित किया था। बाद में संबंधित कामगारों के एक संघ द्वारा समर्थन परिवर्तित किया गया, संदर्भ की तारीख पर एक व्यक्तिगत विवाद क्या था, एक औद्योगिक विवाद और अधिकार क्षेत्र प्रदान करना। द हिंदू विद वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ़ द हिंदू इन मद्रास,1959) ॥ एलएलजे 348 और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ द हिंदू बनाम द हिंदू (1961) 1 एलएलजे 288.

औद्योगिक विवाद-व्यक्तिगत विवाद-यदि और कब औद्योगिक विवाद में परिवर्तित किया जा सकता है-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 1947), एस 12 (5)

निर्णय:

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 22/1961

संदर्भ (आईटी) संख्या 33/ 1959 में औद्योगिक न्यायाधिकरण, बॉम्बे के 3 अक्टूबर, 1959 के फैसले से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से रामास्वामी, ई. उदावरत्नम और एसएस शुक्ला।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए आर. राममूर्ति अय्यर और आर. गोपालकृष्णन।

27 सितंबर 1961. अदालत का फैसला शाह न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

शाह, जे- यह औद्योगिक अधिकरण, बॉम्बे के एक फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति के साथ एक अपील है। अपने फैसले से ट्रिब्यूनल ने इस संदर्भ को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास बॉम्बे सरकार द्वारा प्रस्तुत विवाद पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

सालिवतीश्वरन (तीसरा अपीलकर्ता) जिसने पहले प्रतिवादी का पूर्णकालिक कर्मचारी होने का दावा किया था। द हिंदू", बॉम्बे ने 15 फरवरी, 1956 को मद्रास में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र "द हिंदू" के प्रबंध संपादक को एक पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि वह '1 मार्च, 1956 को यूरोप जा रहे थे। 16 फरवरी, 1956 को "द हिंदू" के सहायक संपादक ने सालिवतीश्वरन को सूचित किया कि भले ही वह 'द हिंदू' के

पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं थे, लेकिन वे अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में "बार-बार ब्रेक की अनुमति नहीं दे सकते" और उन्हें ऐसा करना होगा। यदि वह अपनी व्यवस्था के अनुसार यूरोप चले जाते, तो 1 मार्च 1956 से उन्हें संवाददाता के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता। सालिवतीश्वरन ने 29 फरवरी, 1956 को पत्र लिखकर अपने प्रोजेक्ट को जारी रखा, उन्हें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि वह 1 मार्च, 1956 से "द हिंदू" के संवाददाता नहीं रहे। यूरोप के अपने दौरे से लौटने के बाद, सालिवतीश्वरन, 5 जुलाई, 1956 को, उन्होंने बहाली की मांग की और "द हिंदू" के प्रबंधन से भारत से बाहर उनकी अनुपस्थिति की अवधि को छुट्टी के रूप में मानने का आह्वान किया। "द हिंदू" के प्रबंधन ने उस मांग को मानने से इनकार कर दिया, सालिवतीश्वरन ने धारा के तहत एक आवेदन दायर किया। बॉम्बे वर्किंग जर्नलिस्ट (सेवा की शर्तें) और 1955 के विविध प्रावधान अधिनियम 45 के 17, रुपये का दावा। 1,57,172-8-0 विभिन्न शीर्षकों के तहत आरोप लगाया गया कि उसके रोजगार की समाप्ति गलत थी और यह छंटनी के समान थी। "द हिंदू" के प्रबंधन, ने इस बात से इनकार किया कि सालिवतीश्वरन उनके कर्मचारी थे और प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1955 की धारा 45 के तहत प्राधिकरण के पास तथ्य के विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। प्राधिकरण ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अपने समक्ष मामले में उत्पन्न होने वाले विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेने में सक्षम है।

"द हिंदू" के प्रबंधन ने प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने के निर्देश के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका यह तर्क देते हुए प्रस्तुत की कि अधिनियम की धारा 17 प्राधिकरण को विवादित दावों पर निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं देती है। इस न्यायालय ने प्रबंधन की याचिका को बरकरार रखा, कस्तूरी एण्ड संस (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम सालिवतीश्वरन 1959 एससी आर 1. "द हिंदू" की, लेकिन याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से प्रबंधन के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने आवेदन पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि तथ्य के विवादित प्रश्न उसके समक्ष याचिका में निर्धारित किया जाना था।

"द हिंदू" का 1937 से बंबई में एक कार्यालय था। भौतिक समय में, "द हिंदू" के पास सालिवतीश्वरन के अलावा केवल नौ कर्मचारी-सात प्रशासनिक पक्ष में कार्यरत और दो पत्रकार-वेंकटैयावरन और तिवारी है । सालिवतीश्वरन और वेंकटेश्वरन बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदस्य थे: अन्य पत्रकार कर्मचारी तिवारी यूनियन के सदस्य नहीं थे। बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एक ट्रेड यूनियन है, जिसकी सदस्यता उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो अपनी आजीविका के लिए पत्रकारिता के पेशे पर निर्भर हैं, जिनमें प्रेस फोटोग्राफर, कलाकार, कार्टूनिस्ट और फ्री-लांस

लेखक शामिल हैं। यह संघ निश्चित रूप से "द हिंदू", बॉम्बे के कर्मचारियों का संघ नहीं है, लेकिन यह उन सभी व्यक्तियों का संघ है जो अपनी आजीविका के लिए बॉम्बे में पत्रकारिता पर निर्भर हैं। 16 अगस्त, 1956 के अपने प्रस्ताव द्वारा, बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने धारा के तहत उनके द्वारा दायर आवेदन में सालिवतीश्वरन के दावे का समर्थन किया अधिनियम 1955 संख्या 45 की धारा 17।

9 अप्रैल, 1958 और 15 अप्रैल, 1958 के बीच, संघ के 225 सदस्यों (जिनमें वेंकटेश्वरन शामिल नहीं थे) द्वारा चार पत्र भेजे गए थे, जिसमें संघ को सूचित किया गया था कि सालिवतीश्वरन के रोजगार को समाप्त कर दिया गया है। "सिद्धांत के प्रश्न उठाए और यह आवश्यक था कि एक उचित निर्णय होना चाहिए जिसमें सिद्धांतों को तय किया जा सके" और इसलिए उन्होंने सालिवतीश्वरन के मुद्दे का समर्थन किया और संघ से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे को संदर्भित करने के लिए बॉम्बे राज्य से संपर्क करने के लिए सभी उचित कदम उठाए। न्यायनिर्णयन के लिए एक उपयुक्त न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (1)(सी) ।

संघ का दावा है कि ये पत्र एक बैठक बुलाने की मांग के समान थे और उन्हें 17 अप्रैल, 1958 को डीवी नाथन की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य निकाय की स्थगित बैठक के समक्ष रखा गया था, और उस बैठक में इसे हल किया गया था: "द हिंदू" बॉम्बे के साथ विवाद में

सालिवतीश्वरन के मुद्दे का समर्थन करने के लिए। 25 अप्रैल, 1958 को यूनियन ने "द 'हिन्दू" के मालिक को पत्र लिखा सालिवतीश्वरन द्वारा उठाए गए विवाद को निपटाने के लिए । "द हिंदू" बॉम्बे ने अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, संघ ने हस्तक्षेप करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नियुक्त सुलह अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया। विवाद को सुलह अधिकारी, बॉम्बे द्वारा सुलह के लिए उठाया गया था, लेकिन पक्षों के साथ कई बैठकें करने के बाद, सुलह अधिकारी ने 5 दिसंबर, 1958 की अपनी रिपोर्ट में सुलह लाने के अपने प्रयासों में विफलता की सूचना दी, इसके बाद, 9 फरवरी को, 1959, बॉम्बे राज्य ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(5) के तहत निर्णय के लिए "'द हिंदू", बॉम्बे और सालिवतीश्वरन के बीच विवाद को संदर्भित किया। सरकार का आदेश, जिसका प्रभाव इस मामले में निर्धारण के लिए आता है, इस प्रकार है: -

> "नंबर एजेएन। 7458-एच-जबकि बॉम्बे सरकार ने उप-धारा (4) के तहत सुलह अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का XIV) की धारा 12 के तहत, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित मांगों को लेकर हिंदू, बॉम्बे और इसके तहत कार्यरत श्रमिकों (श्रमिक पत्रकारों) के बीच विवाद के संबंध
>
> में

और जबकि बॉम्बे सरकार उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार कर रही है, संतुष्ट है कि विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजने का मामला है;

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का XIV) की धारा 12 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान की धारा 3 के साथ पढ़ें अधिनियम, 1955 (1955 का XIV), बॉम्बे सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए श्री एमएच मेहर से युक्त ट्रिब्यूनल को संदर्भित करती है, जो सरकारी अधिसूचना, श्रम और समाज कल्याण विभाग, संख्या आईडीए के तहत गठित है। 1157(बी) दिनांक 12 मार्च, 1957।"

अनुसूची के अनुसार, विभिन्न मदों के तहत कुल मिलाकर 1,52,172-8-0 रुपये प्राप्त करने का सालिवतीस्वरन का दावा निर्धारित किया गया था।

"द हिंदू", बॉम्बे ने इस विवाद को संदर्भित करने की राज्य सरकार की क्षमता को तीन आधारों पर चुनौती दी: (1) बॉम्बे में "द हिंदू" का कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं था और इसलिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास

कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। (2) अधिनियम के अर्थ के तहत सालिवतीश्वरन एक कामकाजी पत्रकार नहीं थे और उन्हें "द हिंदू" द्वारा नियोजित नहीं किया गया था, और "द हिंदू" और औद्योगिक सालिवतीश्वरन के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। ट्रिब्यूनल' का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। विवाद पर फैसला सुनाने के लिए और (3) कि एक ओर "द हिंदू" बॉम्बे के वर्किंग जर्नलिस्ट और दूसरी ओर प्रबंधन के बीच कोई विवाद नहीं था और सालिवतीश्वरन द्वारा उठाया गया विवाद केवल एक व्यक्तिगत विवाद था जो था "द हिंदू" बॉम्बे के काफी संख्या में कर्मचारियों द्वारा समर्थित नहीं। ट्रिब्यूनल ने पहले और दूसरे आधार को खारिज कर दिया, लेकिन तीसरे को बरकरार रखा, और यह माना कि यह विवाद केवल सालिवतीश्वरन और "द हिंदू", बॉम्बे के बीच एक व्यक्तिगत विवाद था, जिसे "द हिंदू" के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या द्वारा समर्थन नहीं मिला था। बॉम्बे सरकार के पास विवाद को ट्रिब्यूनल में संदर्भित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

धारा 12(2) के तहत बॉम्बे सरकार द्वारा संदर्भ की शर्तें इस ओर इंगित करता है कि विवाद मुख्य रूप से 'द हिंदू' बॉम्बे और अपीलकर्ता के एक कर्मचारी के बीच था, जो उसके व्यक्तिगत दावे से संबंधित था, जिसमें 'द हिंदू', बॉम्बे के अन्य कर्मचारी सीधे तौर पर रुचि नहीं रखते थे। सेंट्रल प्रोविंस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बनाम रघुनाथ गोपाल पटवर्धन 1956 SCR 956 में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर तीन संभावित विचार स्थापित

करने के बाद कि क्या किसी व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा किए गए विवाद को धारा 2(के) के अर्थ के भीतर एक औद्योगिक विवाद माना जा सकता है । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कहा गया है.. "न्यायिक राय की प्रधानता स्पष्ट रूप से ऊपर बताए गए तीन विचारों में से अंतिम के पक्ष में है (यानी एक नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक हो सकता है यदि इसे संघ या कई कामगारों द्वारा उठाया जाता है और इसके पीछे पर्याप्त कारण हैं। इसके बावजूद धारा 2(के) की भाषा इतनी व्यापक है कि एक नियोक्ता और एक व्यक्ति के बीच विवाद को कवर किया जा सकता है। कर्मचारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम की योजना इस बात पर विचार करती प्रतीत होती है कि इसमें प्रदान की गई मशीनरी को गति में सेट किया जाना चाहिए, केवल उन विवादों को निपटाने के लिए जिनमें एक वर्ग के रूप में श्रमिकों के अधिकार शामिल हैं और एक श्रमिक के व्यक्तिगत अधिकार को छूने वाला विवाद अधिनियम के तहत निर्णय का विषय बनने का इरादा नहीं था, संघ या अनेक श्रमिकों द्वारा यह दृष्टिकोण द न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण यूपी, में दोहराया गया था इसलिए व्यक्तिगत विवाद के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रयोज्यता को श्रमिकों के एक समूह से जुड़े विवाद से अलग रखा गया है, जब तक कि कामगार: एक निकाय या उनका एक बड़ा वर्ग इसके साथ आम कारण नहीं बनता है।

व्यक्तिगत कमर्चारी वर्तमान मामले में यह विवाद, प्रथम दृष्टया, एक व्यक्तिगत विवाद है, इसलिए यह एक औद्योगिक विवाद बन सकता है, यह स्थापित करना बुरा होगा कि इसे "द, हिंदू", बॉम्बे के कर्मचारियों के संघ द्वारा उठाया गया था। "द हिंदू", बॉम्बे के काफी संख्या में कर्मचारियों द्वारा। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस विवाद को बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स द्वारा समर्थित किया गया था, जिसके सालिवतीश्वरन सदस्य थे और किसी भी घटना में, इसे वेंकटेश्वरन और तिवारी का समर्थन प्राप्त था, जो इस प्रतिष्ठान में एकमात्र अन्य कर्मचारी थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजे जाने के बाद इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा उठाया गया, यह एक औद्योगिक विवाद बन गया है।

अपने संविधान के अनुसार बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स किसी एक नियोक्ता के कर्मचारियों का नहीं, बल्कि बॉम्बे में पत्रकारिता उद्योग के सभी कर्मचारियों का संघ है। संघ द्वारा इस मुद्दे का समर्थन, हमारे निर्णय में, इसके किसी सदस्य के व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में परिवर्तित नहीं करेगा।' "द हिंदू", बॉम्बे और सालिवतीश्वरन के बीच विवाद रोजगार की कथित गलत समाप्ति के संबंध में था; यह एक औद्योगिक विवाद का स्वरूप तभी प्राप्त कर सकता है जब यह साबित हो जाए कि इसे संदर्भित किए जाने से पहले, इसे "द हिंदू", बॉम्बे के कर्मचारियों के संघ द्वारा समर्थित किया गया था।

इसके कर्मचारियों की प्रशंसनीय संख्या। दिमाकुची टी एस्टेट के कामगारों बनाम दिमाकुची टी एस्टेट के प्रबंधन में इस न्यायालय ने बहुमत से माना कि एक औद्योगिक के दो परीक्षण उप धारा । (के) द्वारा परिभाषित विवाद हैं। इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 में यह होना चाहिए- (1) विवाद एक वास्तविक विवाद होना चाहिए जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई राहत द्वारा निपटाया जा सके और (2) वह व्यक्ति जिसके संबंध में विवाद हो उठाया गया मामला ऐसा होना चाहिए जिसके रोजगार, गैर-रोजगार, रोजगार की शर्तों, या श्रम की शर्तों (जैसा भी मामला हो) में विवाद के पक्षों का प्रत्यक्ष या पर्याप्त हित हो, और यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए प्रत्येक मामले का. उस मामले में, कुछ कर्मचारियों ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में विवाद खड़ा करने की कोशिश की जो कामगार नहीं था। वर्तमान मामले में संघ के सदस्य, जो नियोक्ता के कर्मचारी नहीं थे, जिनके खिलाफ विवाद खड़ा करने की मांग की गई थी, विवाद का समर्थन करके प्रथम दृष्टया व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में बदलना चाहते हैं। यह सिद्धांत कि जो व्यक्ति किसी श्रमिक के हितों का समर्थन करना चाहते हैं, उन्हें सीधे और पर्याप्त रूप से विवाद में रुचि होनी चाहिए, हमारे विचार में यह मामलों के इस वर्ग पर भी लागू होता है: जो व्यक्ति कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें उसी नियोक्ता के रूप में नहीं माना जा सकता है। इतनी रुचि रखते हैं कि अपने समर्थन से वे एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में बदल सकते

हैं। इसलिए बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स द्वारा उनके मुद्दे का समर्थन मात्र सलिवतेश्वरन के दावे को मदद नहीं कर सकता है ताकि इसे एक औद्योगिक विवाद में बदल दिया जा सके।

लेकिन अपीलकर्ताओं के वकील का कहना है कि वेंकटेश्वरन बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदस्य हैं, उस यूनियन द्वारा इस मुद्दे का समर्थन करना वेंकटेश्वरन द्वारा इस मुद्दे का समर्थन करना है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वहां केवल तीन कर्मचारी थे जो "द हिंदू" बॉम्बे के पत्रकार थे, जिनमें से वेंकटेश्वरन ने इस मुद्दे का समर्थन किया था, इस विवाद ने एक औद्योगिक विवाद का रूप ले लिया। यह सच है कि बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की कार्यकारी समिति ने अगस्त 1956 में सालिवतीश्वरन के मुद्दे का समर्थन करने का संकल्प लिया था, लेकिन वह संकल्प 1955 के अधिनियम की संख्या 45 के तहत याचिका में बॉम्बे और इस न्यायालय में भी आवेदन के संबंध में था। यूनियन सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुई । संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत , वह समर्थन, हमारे फैसले में, सालिवतीश्वरन द्वारा किए गए दावे का समर्थन नहीं कर सकता। जब प्राधिकरण ने याचिका पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो वर्किंग जर्नलिस्ट (सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 17 समाप्त हो गई। फिर, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वेंकटेश्वरन ने इनमें से किसी भी कार्यवाही में भाग लिया था। वेंकटेश्वरन और तिवारी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष हलफनामा दायर किया जिसमें कहा

गया कि सालिवतीश्वरन और "द हिंदू" के प्रबंधन के बीच विवाद पूरी तरह से पूर्व का व्यक्तिगत मामला था और उन्होंने विवाद के संबंध में उनके साथ सामान्य कारण नहीं बनाया था या उनके स्वंय के विवाद को अपनाया नहीं था। वेंकटेश्वरन और तिवारी ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने कभी भी सालिवतीश्वरन के दावे का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया है। वेंकटेश्वरन ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी भी समय बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स को सालिवतीश्वरन का मामला उठाने और उस पर विवाद उठाने के लिए अधिकृत नहीं किया था। वेंकटेश्वरन और तिवारी द्वारा दायर हलफनामे लगभग समान शब्दों में थे और यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कर्मचारियों ने मिलकर काम किया था, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जैसा कि सालिवतीश्वरन ने तर्क दिया, उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए मजबूर किया गया था।

अपीलकर्ताओं के वकील ने 17 अप्रैल, 1958 को बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की एक असाधारण बैठक में पारित एक प्रस्ताव पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसमें धारा के तहत "द हिंदू" के खिलाफ सालिवतीश्वरन के विवाद को उठाया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 में "छंटनी किये गये पत्रकार सालिवतीश्वरन" के लिए राहत की मांग की गई है। लेकिन इस प्रस्ताव के समर्थन में साक्ष्य बहुत असंतोषजनक हैं। वर्तमान में बताए जाने वाले कारणों के लिए, हमारा विचार है कि साक्ष्य

पहले प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलील को स्थापित करते हैं कि कथित समाधान का रिकॉर्ड सालिवतीश्वरन के मामले का समर्थन करने की दृष्टि से गढ़ा गया था।

17 अप्रैल, 1958 की कथित बैठक संघ की असाधारण आम बैठक के रूप में नहीं बुलाई गई थी। दावा किया गया है कि यह एक स्थगित बैठक थी, पिछली बैठक 5 अप्रैल, 1958 को आयोजित की गई थी और स्थगित कर दी गई थी। महातमे - प्रासंगिक समय पर संघ के सचिव ने बताया कि एक बैठक बुलाने के लिए एक मांग प्राप्त हुई थी, 17 अप्रैल, 1958 की बैठक में मांग पर विचार किया गया था, और सालिवतीस्वरन के मामले का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि बैठक का एजेंडा उपलब्ध नहीं है और वह बैठक में जो कुछ हुआ, उसके बारे में स्मृति से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंडे की साइक्लोस्टाइल प्रतियां थीं जिन्हें नष्ट कर दिया गया और कोई प्रतियां नहीं रखी गईं; कि 17 अप्रैल की बैठक का कोई एजेंडा नहीं था और नोटिस की कोई प्रतियां नहीं रखी गई थीं; सामान्य निकाय की बैठक का कोई विवरण नहीं रखा गया था और यह दिखाने के लिए लिखित रूप में कुछ भी नहीं था कि 5 अप्रैल और 17 अप्रैल की बैठकों में कौन शामिल हुआ था और, 'सामान्य निकाय की बैठकों में जो कुछ भी होता है वह वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है।" उन्होंने स्वीकार किया कि 5 अप्रैल के बाद अधियाचनाएं प्राप्त हुईं और संघ के नियमों के अनुसार, बैठक

बुलाने के लिए 15 दिनों का नोटिस आवश्यक था। उन्होंने कहा कि उन्हें 17 अप्रैल से पहले सभी अधियाचनाएं प्राप्त हुई थीं, लेकिन उनकी प्राप्ति के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। महाटेम के अनुसार, 225 सदस्यों ने मांग पर हस्ताक्षर किए थे और बैठक में उन्होंने इस मामले को उठाने के लिए कहा था, लेकिन इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि कौन उपस्थित था। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल की बैठक का नोटिस जारी किया गया था लेकिन वह यह नहीं बता सके कि यह 9 अप्रैल को जारी किया गया था या उसके बाद। महाटेम की गवाही को स्वीकार करना मुश्किल है कि भले ही कार्यकारी समिति की बैठकों के मिनट बनाए रखे गए थे, लेकिन सामान्य निकाय की बैठकों से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित नहीं किए गए थे। महाटेम का यह स्पष्टीकरण कि एजेंडा को साइक्लोस्टाइल किया गया और उसके बाद नष्ट कर दिया गया, स्वीकार करने के लिए बहुत अपरिष्कृत है। अन्य परिस्थितियाँ जिनके बारे में हम वर्तमान में चर्चा करेंगे, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं कि 17 अप्रैल, 1958 को प्रस्ताव पारित होने की कहानी झूठी है।

मूल संकल्प को परीक्षण के दौरान विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। प्रर्दश यू-86. इस दस्तावेज़ में अंतर्निहित साक्ष्य हैं कि यह 17 अप्रैल, 1958 को नहीं बनाया गया था। यह 17 अप्रैल, 1958 का बताया जाता है और इस पर राष्ट्रपति डीवी नाथन के हस्ताक्षर हैं, लेकिन कुछ संयोग से वर्ष मूल रूप से 1959 लिखा गया था और फिर 1958 में बदल

दिया गया। यह बहुत अच्छी तरह से संकेत दे सकता है कि लेखक 1959 में लिख रहा था, 1958 में नहीं। डीवी नाथन, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की थी, से पूछताछ नहीं की गई है। महातमे ने कहा कि वर्ष 1957-58 की वार्षिक रिपोर्ट, जो वर्ष 1958 के अंत में किसी समय प्रकाशित हुई थी, में 17 अप्रैल, 1958 की बैठक का जिक्र है, लेकिन रिपोर्ट में 5 अप्रैल की बैठक का जिक्र है, और 17 अप्रैल की बैठक का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। सदस्यों के पत्र वास्तव में मांगें नहीं हैं: वे केवल कुछ सदस्यों द्वारा सालिवतीश्वरन के मुद्दे का समर्थन करने के लिए संघ से किए गए अनुरोध हैं, और सचिव से बैठक बुलाने का अनुरोध नहीं करते हैं। यदि नियमों के अनुसार कोई मांग वास्तव में प्राप्त हुई थी, तो उस उद्देश्य के लिए 15 दिनों के नोटिस के बाद एक बैठक बुलानी होगी। बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की आम सभा की बैठकों के संविधान और नियमों के क्लॉज 7(सी) की आवश्यकता है 15 दिन का स्पष्ट नोटिस, सिवाय इसके कि जब कोई बैठक स्थगित कर दी गई हो, ऐसी स्थिति में एक सप्ताह का नोटिस पर्याप्त होगा। यह क्लॉज द्वारा भी प्रदान किया जाता है। (छ) अन्य व्यवसाय के संबंध में प्रस्ताव जिसे कोई सदस्य किसी बैठक में लेना चाहता हो, उसे भी बैठक से सात दिन पहले दिया जाना चाहिए। क्लॉज 19 के तहत सामान्य निकाय की बैठक की सूचना क्लॉज में निर्धारित समय के भीतर सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से भेजी जानी है। संविधान के क्लॉज 7, और

18, उप-क्लॉज. 2 (ए), सचिव को सभी बैठकों के कार्यवृत्त को बनाए रखना होगा, सभी पत्राचार का संचालन करना होगा, सभी बैठकें बुलानी होंगी, संघ के मामलों और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण करना होगा। 17 अप्रैल, 1958 की कथित बैठक में 15 दिनों की स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। अन्य व्यवसाय से संबंधित प्रस्तावों के बारे में जिन्हें कोई सदस्य 7 दिनों की किसी भी बैठक में लेना चाहता है, नियमों के अनुसार स्पष्ट सूचना की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सामान्य निकाय की बैठक के लिए क्लॉज 7 के तहत निर्धारित समय की सूचना सदस्यों को दी गई है, और सचिव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि बैठक के किसी भी मिनट का रखरखाव नहीं किया गया था, लेकिन प्रस्ताव को कागज की एक ढीली शीट पर कॉपी कर दिया गया था। संघ के पदाधिकारियों का बाद का आचरण भी प्रतिवादियों के वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क का दृढ़ता से समर्थन करता है कि यह प्रस्ताव किसी बाद की तारीख में गढ़ा गया है। 25 अप्रैल, 1958 को लिखे पत्र में कहा गया था कि बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने सालिवतीश्वरन के विवाद को उठाया था और "द हिंदू", बॉम्बे से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का आह्वान किया था, लेकिन पारित प्रस्ताव का कोई संदर्भ नहीं है। 17 अप्रैल, 1958 को औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष दावे के बयान में भी संकल्प का उल्लेख नहीं किया गया था। दावे के बयान के पैरा 33 में यह कहा गया था कि संघ के 200 से अधिक सदस्यों ने श्रमजीवी

पत्रकार (सालिवतीश्वरन) का समर्थन करते हुए इस संघ को पत्र लिखा था और संघ से उनके मामले को उठाने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 अप्रैल, 1958 की अपील । द हिंदू" ने अपने उत्तर के पैराग्राफ 4 में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बयान के अलावा कि संघ के 225 सदस्यों ने अपने सचिव से सालिवतीश्वरन का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया था, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि संघ इसने कोई प्रस्ताव पारित किया था या अपने सचिव को सालिवतीश्वरन का मामला उठाने और उस पर औद्योगिक विवाद खड़ा करने के लिए अधिकृत किया था। "द हिंदू" के इस बयान को जवाब में एक हलफनामे द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सालिवतीश्वरन के दावे को एक प्रस्ताव द्वारा समर्थित किया गया था। संघ के। जब 12 जून, 1959 को वेंकटेश्वरन की जांच की गई, तो उनसे जिरह में प्रस्ताव के बारे में नहीं पूछा गया। यहां तक कि जब सालिवतीश्वरन की जांच की गई तो भी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया: यह पहली बार 9 जुलाई, 1959 को पेश किया गया था। सालिवतीश्वरन के मुद्दे का समर्थन करने के लिए संघ से अनुरोध करने वाले पत्र 9 अप्रैल और 15 अप्रैल, 1958 के बीच लिखे गए थे, और यह सुझाव दिया गया है कि मामला 17 अप्रैल की बैठक में उठाया गया था। यदि 17 अप्रैल की बैठक एक स्थगित बैठक थी (पिछली बैठक 5 अप्रैल को होने के कारण एजेंडे में इन पत्रों पर विचार का कोई संदर्भ नहीं हो सका और नये मामले नहीं उठाये जा सके। सालिवतीश्वरन की रुचिपूर्ण गवाही

द्वारा समर्थित महातमे के नंगे बयान के अलावा, कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि 17 वीं बैठक में सचिव ने सालिवतीश्वरन के बारे में प्रस्ताव पेश किया और इसे बिना किसी विरोध के दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपनाया गया, जो सामान्य रूप से अस्तित्व में होना चाहिए था। यह मामला कि संघ ने 17 अप्रैल, 1958 को एक प्रस्ताव पारित किया था, सच था, इस दलील पर पेश नहीं किया गया कि या तो इसका रखरखाव नहीं किया गया' या कि इसे नष्ट कर दिया गया। अपीलकर्ताओं के मामले में भी, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मांग पर विचार करने के उद्देश्य से 17 अप्रैल को बुलाई गई बैठक का नोटिस कभी वेंकटेश्वरन को दिया गया था और यदि नहीं दिया गया था, तो केवल एक प्रस्ताव पारित करके। संघ के अन्य सदस्यों के अपीलकर्ताओं के मामले का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि सालिवतीश्वरन के दावे का समर्थन वेंकटेश्वरन ने किया था।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि यदि संदर्भ के बाद भी वेंकटेश्वरन और तिवारी ने सालिवतीश्वरन के कारण का समर्थन करना बंद कर दिया, एकमात्र व्यक्ति जो कारण का समर्थन कर सकता है, तो संदर्भ विफल हो जाना चाहिए, और उस दृष्टिकोण के समर्थन में एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया गया । द हिंदू बनाम द वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ द हिंदू इन मद्रास 1959 11 एलएलजे 348 मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने, इस फैसले को वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ द हिंदू बनाम द हिंदू 1961 1 एलएलजे 288 मामले में मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. उस

मामले में न्यायालय ने कहा यह माना जाना चाहिए कि मामले को आगे बढ़ाने का श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि निर्णय के लिए उसके पास भेजा गया औद्योगिक विवाद अस्तित्व में था या संदर्भ की तारीख पर पकड़ा गया था, न कि किसी पर अगली तारीख. प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह माना जाना चाहिए कि श्रम न्यायालय का किसी औद्योगिक विवाद पर आगे बढ़ने और फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र तब तक कायम रहता है, जब तक कि वह कोई फैसला नहीं दे देता है और वह संदर्भ द्वारा ही लागू करने योग्य नहीं हो जाता है। संदर्भ की तारीख पर मौजूद या आशंका वाले औद्योगिक विवाद के आधार पर किया गया है और मामले में आगे बढ़ने के लिए श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी भी तरह से इस तथ्य से प्रभावित नहीं है कि संदर्भ की तारीख के बाद, कार्यकर्ता या उनका एक बड़ा वर्ग, जिन्होंने मूल रूप से इस मुद्दे को प्रायोजित किया था, बाद में इससे मुकर गए और इससे पीछे हट गए।" हमारे विचार में, इन टिप्पणियों ने पहले से उनके द्वारा समर्थित एक कारण के श्रमिकों द्वारा बाद में समर्थन वापस लेने के प्रभाव को सही ढंग से निर्धारित किया है प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी व्यक्तिगत विवाद ने औद्योगिक विवाद का स्वरूप प्राप्त कर लिया है, परीक्षण यह है कि क्या संदर्भ की तिथि पर प्रतिनियुक्त को नियोक्ता के श्रमिकों के संघ द्वारा समर्थित माना गया था, जिसके खिलाफ विवाद एक अकेले कामगार द्वारा या काफ़ी संख्या

में कामगार द्वारा उठाया जाता है। यदि वेंकटेश्वरन या तिवारी ने संदर्भ की तारीख से पहले सालिवतीश्वरन के कारण का समर्थन किया होता, तो उनके बाद के हलफनामों द्वारा संदर्भ को अमान्य नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वास्तव में, वेंकटेश्वरन या तिवारी द्वारा सलिवतेश्वरन के मुद्दे का कोई समर्थन नहीं किया गया था और इसलिए यह विवाद एक व्यक्तिगत विवाद बना रहा।

इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा सालिवतीश्वरन के मुद्दे को समर्थन का प्रभाव और उस पर स्थापित दावे पर किसी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है। संदर्भ प्रस्तुत किए जाने और ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई लंबित होने के बाद 16 अप्रैल, 1959 को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष द्वारा बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के महासचिव को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि फेडरेशन ने समर्थन दिया था। उच्चतम न्यायालय में "द हिंदू" द्वारा दायर रिट याचिका में सालिवतीश्वरन को बताया गया कि फेडरेशन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक परीक्षण मामला था। 17 अप्रैल, 1959 को एक अन्य पत्र, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के महासचिव द्वारा बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स बॉम्बे के महासचिव को संबोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सालिवतीश्वरन को औद्योगिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष याचिका दायर करने की सलाह दी थी। बॉम्बे में और सुप्रीम कोर्ट में भी हस्तक्षेप किया था, और इसके अलावा फेडरेशन

ने सालिवतीश्वरन को न्याय दिलाने के लिए बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों का पूरा समर्थन किया था, यूनियन के सचिव ने 9 जुलाई, 1959 को पत्र द्वारा राष्ट्रपति को लिखा था। और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के महासचिव ने कहा कि सालिवतीश्वरन के मामले की सुनवाई एक सप्ताह से हो रही थी और सालिवतीश्वरन को अगले दिन जिरह से गुजरना था और पिछले सचिव महातमे को साक्ष्य देना था। हो ने आगे कहा, "मेरी राय है कि हमें कुछ दस्तावेज़ तैयार करने चाहिए जिससे यह साबित करना संभव होगा कि फेडरेशन ने सालिवतीश्वरन के मामले का समर्थन किया था" और फेडरेशन से बैठक के मिनट या पत्र या प्रस्ताव के रूप में एक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया और यदि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं था, तो एक नया पारित करने के लिए सालिवतीश्वरन के मामले के संबंध में बॉम्बे यूनियन की कार्रवाई का समर्थन करने वाला प्रस्ताव और इसे डाक से वापस भेजने का प्रस्ताव। इस पत्र से संकेत लेते हुए, 24 जुलाई, 1959 को फेडरेशन के अध्यक्ष ने कथित तौर पर अपनाए गए प्रस्ताव की एक प्रति भेजी। सालिवतीश्वरन के मामले के संबंध में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की कार्य समिति के सदस्य। मसौदा प्रस्ताव में औद्योगिक न्यायाधिकरण, बॉम्बे के समक्ष बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मामले का समर्थन करने और "संघ को सभी के साथ मामला लड़ने का निर्देश देने" की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव न्यायिक कार्यवाही शुरू होने के बाद

परिसंचरण द्वारा पारित होने का आरोप है। यदि विवाद अपनी शुरुआत में एक व्यक्तिगत विवाद था और बॉम्बे सरकार द्वारा संदर्भ की तारीख तक ऐसा ही जारी रहा, तो यह विवाद में रुचि रखने वाले श्रमिकों के संदर्भ के बाद भी इसे औद्योगिक विवाद में परिवर्तित नहीं किया जा सका। हम पहले ही मान चुके हैं कि बाद में समर्थन वापस लेने से किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र नहीं छिन जाएगा। इसी तर्क के आधार पर बाद का समर्थन संदर्भ के समय एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में परिवर्तित नहीं करेगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का प्रस्ताव, यह मानते हुए कि इसका कोई मूल्य है, व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

हमारे विचार से यह अपील विफल होनी चाहिए और जुर्माने सहित खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दूदा राम खोकर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।